bjpkamaljyoti@gmail.com संवत 2076 युगाब्द 5120 मूल्य : ₹10 अंक – 21, जून प्रथम अंक 2021, कुल पृष्ठ – 32

वर्तमान

कमल ज्योति

सेवा ही संगठन

सेवा ही संगठन
लखनऊ
जालौन
जालौन
अलीगढ़
सेवा ही संगठन
रक्तदान शिविर
कानपुर देहात
जौनपुर

सेवा ही संगठन
दिनांक:-29/5/2021

रक्तदान महादान

सेवा ही संगठन

स्वैच्छिक रक्तदान

स्वैच्छिक रक्तदान

वर्तमान कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार

प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय
कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक
नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

संपादकीय

गांवों की डगर पर सेवा ही संगठन

क्हा जाता है कि 'मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है', जो किसी–न–किसी 'राज्य' के अंतर्गत रहता है, अर्थात एक सामूहिक राजनीतिक सत्ता के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करता है ताकि वह 'उत्तम जीवन' और 'आत्म–सिद्धि' को प्राप्त कर सके। इस प्रकार राजनीति मनुष्य के स्वाभाविक गतिविधि का क्षेत्र माना जाता है। जिसके पीछे एक धारणा कार्य करती है कि राजनीति सेवा के लिये होती है। लेकिन, आम लोगों के लिये राजनीति अच्छी नहीं है। आम लोगों को लगता है कि, राजनीति का स्तर गिर रहा है। परिवारवाद और पैसावाद का जोर है।

लेकिन, राजनीतिक धरा पर इतनी बुराईयों के बीच भारत में ही नहीं वरन् संपूर्ण विश्व के सामने भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का नया स्वरूप प्रस्तुत किया है जिसमें सेवा,साधना और समर्पण की भावना अंतर्निहित है। कोबिड–19 के इस संकटकाल में भाजपा के कार्यकर्त्ताओं ने हजारों यूनिट रक्त देकर लोगों के प्राणों की रक्षा की है। अपने जीवन की चिंता न करते हुये कोबिड ग्रस्त लोगों तक उपचार के साधनों को पहुंचाया है। गांव–गली के अपनों–बेगानों तक भोजन का निवाला पहुंचाया है। करोड़ों हाथों को दवा, मास्क, सेनीटाइजर, राशन, भोजन देकर उनको अपना बनाया है। यही तो सेवा का संगठन मार्ग है। अपनों के आंसू पोंछने की बजाये दूसरों के दुःख में सहभागी बनकर उनका साध्य तय करना है राजनीति का सेवा भाव है। भाजपा आज इसी मार्ग पर चल रही है। समाज के लोगों तक भाजपा का यह सेवा भाव उनके अंर्तमन को झिंझोर कर राजनीति को सेवा की कडी बना चुका है।

इसी लक्ष्य को लेकर आज भाजपा सेवा ही संगठन अभियान के तहत एक लाख गांवों में कोविड से संबंधित विशेष राहत व बचाव अभियान चला रही है। एक लाख गांव तक पहुंचने के लिए केंद्रीय नेताओं से ले कर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की टोली निकल रही है। पार्टी सांसदों और विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों व राज्यों के मंत्रियों संगठन पदाधिकरियों को कम से कम दो गांवों में इसी प्रकार के अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पार्टी इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री और सैनिटाइजर, मास्क और आक्सीमीटर के साथ–साथ कोरोना से निपटने में काम आने वाली वस्तुएं वितरित करेगी। टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करेगी।

दरअसल राजनीति को लेकर आम लोगों की धारणा अलग है। वे अपने व्यक्तिग्त अनुभवों एवं दैनिक खबरों से अपनी राय बनाते हैं। जब एक साधारण आदमी दल–बदल, झूठे वायदे या घोटालों में पकड़े जाते देखता है तब राजनीति उसके लिए बुरी चीज बन जाती है, क्योकि उसकी समझ में राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वह कई बार राजनेताओं को अच्छे कृत्य करते हुए भी देखता है, इसलिए राजनीति के अंतर्गत ही उसे श्रेष्ठ जीवन की संभाव्यता भी दिखाई देती है। इस प्रकार आम लोगों के लिए राजनीति परस्पर विरोधी दावों का सम्मिश्रण है। चूंकि ज्यादातर बार नकारात्मक छवियाँ ही उभर कर सामने आतीं हैं इसलिए आम–जनमानस में 'राजनीति खराब शरण–स्थली' के रूप में जानी जाती है। परंतु यदि हम राजनीति से घृणा करेंगे और उससे दूर रहेंगे तो राजनीति निश्चित रूप से गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी तथा वे अपने हितों और स्वार्थों को सार्वजनिक समस्याओं से ऊपर रखेंगे और जो राजनीति वास्तव में श्रेष्ठ जीवन की संभाव्यता का स्रोत है वह नारकीय जीवन का कारण बन जाएगी।

इसलिये राजनीति को सर्वश्रेष्ठ कृत्य के रूप में भारतीय समाज और जनमानस के समक्ष भाजपा ने अप्रतिम रूप से रखा है। भाजपा ने बताया है कि, राजनीति केचल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है अपितु राजनीति सेवा का मार्ग भी है। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्त्ताओं,पदाधिकारियों और संगठकों ने समाज के अंदर अपने सेवा भाव से इस सकारात्मक छवि को बनाया है। इस छवि को सदैव संजोकर रखना है इसको धूमिल नहीं होने देना है। सेवा के पथ पर चलकर राजनीति के कंटकाकीर्ण मार्ग को कमल के फूलों से पुष्पित और पल्लवित करते जाना है।

इस धाराणा के साथ विदा–पुर्नमिलनाय!

akatri.t@gmail.com

प्रधानमंत्री बोले-वायरस म्यूटेट होने की आगे आशंका, चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 18 जून को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। यह क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां ला सकता है। वायरस अभी भी हमारे बीच है। इसके म्यूटेट होने की आशंका भी है। इसलिए आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए देश को तैयार करना होगा। इसीलिए आज एक लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयार करने का महाभियान शुरू हो रहा है।

1. एक लाख युवा होंगे ट्रेंड

कोरोना से लड़ रही फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश के एक लाख युवाओं को ट्रेंड करने का निर्णय किया है। यह काम दो–तीन महीने में ही हो जाएगा, इसलिए यह तुरंत ही उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। छह कस्टमाइज कोर्स लान्च किए जा रहे हैं। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंट लाइन फोर्स को नई मदद मिलेगी।

2. स्किल, रीस्किल और अपस्किल का मंत्र

अब स्किल, रीस्किल और अपस्किल यह मंत्र बहुत मददगार होगा। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्किल को वैल्यूएड करना अपस्किल है और इस समय इसी की मांग है। स्किल, रीस्किल और अपस्किल के महत्व को समझते हुए देश में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया है। पहली बार अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया। केंद्र और ITI खोलना, उनमें लाखों नई सीटें जोड़ना इस पर लगातार काम किया गया।

3. पैरा मैडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस

इस बात की देश में बहुत चर्चा नहीं हो पाई कि स्किल इंडिया के इस प्रोग्राम ने देश को कितनी बड़ी ताकत दी। जब से कोरोना की चुनौती हमारे सामने आई है, तब से कौशल विकास मंत्रालय ने लोगों को ट्रेंड करने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। साथियों हमारी जनसंख्या को देखते हुए पैरा मैडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं में बीते कुछ वर्षों में बहुत फोकस तरीके से काम किया गया है।

4. हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का काम जारी

नए एम्स और नए नर्सिंग कालेज के काम पर बहुत बल दिया गया है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जिस गति से हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का काम चल रहा है, वह बहुत अभूतपूर्व है। आशा, ANM और गांव–गांव में तैनात हमारे कर्मचारी, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विषम हो, ये साथी अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

5. युद्ध स्तर पर कोरोना से जंग जारी

कोरोना महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क किया है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक वेंटिलेटर्स, आक्सीजन कन्संट्रेटर्स तेज गति से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डेढ़ हजार से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

6. ट्रेनिंग के दौरान और बाद में फायदे

फ्रंटलाइन वर्कर्स के खास ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों को फ्री ट्रेनिंग के साथ खाने और रहने सुविधा, स्टाइपेंड, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट और सर्टिफाइड उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा।

फ्रंटलाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार DSC/SSDM की व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में काम कर सकेंगे।

7. कोरोना वारियर्स को सशक्त करेंगे

इस प्रोग्राम का तात्पर्य है कि देशभर में एक लाख से अधिक कोरोना वारियर्स को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। कोरोना वारियर्स को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 टास्क से जुड़े रोल के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

इस प्रोग्राम के लिए 276 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत आने वाला प्रोग्राम है, जिसे खासतौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रमशक्ति की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर–चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार करेगा।

कोविड हेल्पलाइन सेंटर्स का उद्घाटन

देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकार्ड सरकारी खरीद हुईः जगत प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 जून शुक्रवार को 'सेवा ही संगठन 2.0 के तहत भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में देश भर में शुरू किये जा रहे कोविड हेल्पलाइन सेंटर्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर के साथ—साथ प्रदेशों की टीम एवं सामुदायिक केन्द्रों से किसान मोर्चा के कोविड हेल्पलाइन सेंटर्स भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। ज्ञात हो कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर भाजपा किसान मोर्चा ने देश भर में लगभग 658 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। श्री नड्डा ने राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में गठित भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को नई पारी की शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के विषय में किसानों को जागरुक करने के लिए 'किसान जन—जागरण अभियान — आत्मनिर्भर किसान अभियानश चलाया था और किसानों को कृषि विधेयकों के लाभ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। इस अभियान में देश भर में लगभग 8581 स्थानों पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण पूजन किया गया तथा 550 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं आयोजित की गई। समाज के प्रबुद्धजनों से संवाद किया गया। कृषि कानूनों के संबंध में शोध एवं आलेख प्रकाशित किये गए। कृषि कानूनों को सरल भाषा में समझाने के लिए पैम्फलेट बांटे गए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों के समर्थन में पोस्टकार्ड प्रेषित किए गए। मैं इसके लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत—बहुत साधुवाद देता हूँ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं आज सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 मई 2021 को 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक एकाउंट में डीबीटी के माध्यम से इस योजना की आठवीं किस्त के रूप में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि ट्रांसफर करने के लिए बहुत—बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुँच चुकी है। इनमें से केवल कोरोना काल में ही चार किस्तों में 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचे हैं। हमारे लिए हर्ष का विषय यह भी है कि पहली बार बंगाल के लाखों किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने परसों, बुधवार,19 मई को ही खाद सब्सिडी बढ़ाने का

ऐतिहासिक निर्णय लिया है। DAP खाद पर सब्सिडी 140: बढ़ा दी गई है। किसानों को व।च पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अब 1,200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को व।च का एक बैग 2,400 रुपये के बजाय अब 1,200 रुपये में ही मिलेगा। सरकार इस पर 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से ही किसानों की आय बढ़ाने और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, स्वायल हेल्थ कार्ड इत्यादि अनेकों योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी लगातार अन्नदाताओं को मजबूती दे रहे हैं।

समर्थन मूल्य पर बोलते हुए कहा कि श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद जारी है। पंजाब से इस बार सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। सबसे अधिक गेहूं पंजाब से 132 लाख 10 हजार टन खरीदा गया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा तय खरीद लक्ष्य से यह 2 लाख मीट्रिक टन अधिक है। पंजाब के इतिहास में रबी मार्केटिंग सीजन 2021–22 में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई। 9 लाख से अधिक किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे 23 हजार करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन फिर भी ये लोग एमएसपी का रोना रोयेंगे। एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं है। एमएसपी था, है और रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं कई बार इसे दोहराया है। मोदी सरकार एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेज रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके और आढ़तियों के चंगुल से किसानों को निकाला जा सके। इस बार एमएसपी से लगभग 34 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है और उनके एकाउंट में लगभग 60,000 करोड़ रुपये पहुँच चुके हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रिकार्ड खरीद हो रही है तो उम्मीद है कि निर्यात का आंकड़ा इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर होगा। निर्यात बढ़ने से किसानों को ज्यादा लाभ होगा और उन्हें आने वाले समय में पैदावार की अच्छी कीमत मिलेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि देश में पहली बार मोदी सरकार ने 'एक देश, एक कृषि बाजार' बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। देश में पहली बार किसानों को अपनी फसल कहीं पर, किसी को भी बेचने की आजादी मिली। देश में पहली बार किसानों की भलाई के लिए उत्पोदन लागत का न्यूचनतम डेढ़ गुना एमएसपी निर्धारित की गई। देश में पहली बार किसान रेल, कृषि उड़ान और किसान चौनल की शुरुआत हुई। देश में पहली बार उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाया गया। देश में पहली बार मोदी सरकार ने ''पेड़'' की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया। देश में पहली बार किसानों के लिए अंतरराज्यीय व्यापार प्लेटफॉर्म म–छ।ड की शुरुआत मोदी सरकार ने की।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह मोदी सरकार है जिसने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सेक्टनर के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री–इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जारी किया। देश में पहली बार पीएम किसान मानधन योजना शुरू की गई जिसके तहत देश के किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन की सुविधा है। मोदी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 'आपरेशन ग्रीन्स' की शुरुआत की।

श्री नड्डा ने कहा कि आज से 7 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं मोदी सरकार में इसकी संख्या बढ़कर तीन हो गई है। पिछले ही साल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमारी सरकार ने 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना का कार्य शुरू किया है। वोकल फार लोकल की नीति पर चलते हुए 'एक जिला–एक उत्पाद' योजना शुरू किया गया है ताकि भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बन सके।

सेवा ही संगठन 2.0 अभियान

मोदी सरकार की तत्परता से हम संक्रमण दर को कम रखने में सफल रहे : जगत प्रकाश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय स्वागत योग्य

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 जून शुक्रवार को 'सेवा ही संगठन 2.0 के तहत कोविड के खिलाफ दुनिया के बाकी देशों में सरकार ने लड़ाई लड़ी जबकि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ देशवासियों को साथ में लेकर लड़ाई लड़ी। जब कोरोना की दूसरी लहर ने हमें घेरा तो हमने अविलंब 'सेवा ही संगठन पार्ट 2.0 का अभियान शुरू किया और पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपनी फिक्र न करते हुए दिन–रात अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और प्रशासन के साथ मिल कर जरूरतमंदों के लिए बेड्स, दवाइयां, आक्सीजन सिलिंडर और भोजन की व्यवस्था में लगे हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि सेवा ही संगठन 2.0 अभियान के तहत अब तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में 1,250 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। भाजपा ने जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला स्तर तक 3,200 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हेल्पलाइन सेंटर्स स्थापित किया है। सेवा ही संगठन के दूसरे चरण में अब तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने 65 लाख से अधिक फेस मास्क, 14 लाख से अधिक फूड पैकेट्स, 07 लाख से अधिक राहत सामग्री और बड़ी संख्या में इम्युनिटी किट्स का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन 2.0 में टीकाकरण के कार्य में भारतीय जनता पार्टी के 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता लगे हैं। मैं सेवा कार्य में लगे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। इस दौरान पार्टी ने 3,000 से अधिक समीक्षा बैठकें की हैं और पार्टी की बूथ स्तर तक की टीमों को मानवता की सेवा के लिए एक्टिव किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी कड़ी में किसान मोर्चा की की पहल मानवता की सेवा का बड़ा माध्यम सिद्ध होगा इससे खास कर गाँव के गरीब लोगों को कोविड से लड़ाई में काफी फायदा होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोविड संक्रमण आने के बाद प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फेस मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स के उत्पादन में भारत

आत्मनिर्भर बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर जिले में आक्सीजन प्लांट स्थापित किये जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से मदद दी जा रही है। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए दवाइयों, आक्सीजन, वेंटीलेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरणों की अबाध आपूर्ति की जा रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में काफी प्रगति की है। हमारी टेस्टिंग फेसिलिटी जहां पहले 1,500 पर दिन की थी, वह अब लगभग 25 लाख प्रतिदिन हो गई है। जहां पहले टेस्टिंग के लिए देश में पुणे में एक ही लैब था, वहीं अब ये आंकड़ा लगभग 2,500 हो गया है। आज आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़ कर 14 लाख से अधिक हो गई है। इसी तरह प्ब् बेड्स की संख्या 2,168 से बढ़ कर 81 हजार हो गई है। अब तक केंद्र द्वारा राज्यों को लभग 85 लाख पीपीई किट्स और 4 करोड़ से अधिक छ—95 मास्क का वितरण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोविड के संक्रमण काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर शुरू किया गया पीएम केयर्स फंड जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, अस्थायी अस्पताल और आरटीपीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इस फंड से सहयाता प्रदान की जा रही है। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल आक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर खरीदे जायेंगे। कोबिड—19 टीकों के परीक्षण और रिलीज के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) के उन्नयन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान की दो प्रयोगशालाओं को भी पीएम केयर्स फंड से वित्तीय मदद दी गई। विभिन्न मदों में राज्यों को भी इससे मदद दी जा रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी 2021 से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आरंभ हुआ। भारत सरकार द्वारा अब तक 18.70 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में मुहैया कराये गये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी एनडीए शासित राज्यों ने मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय लिया है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वैक्सीन लग सके। कांग्रेस आज वैक्सीनेशन के लिए चिट्ठियां लिख रही है लेकिन अच्छा होता कि ये अपने मुख्यमंत्रियों को मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए चिट्ठी लिखती।भाजपा सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ चल रही है। हमारी सरकारों द्वारा मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय इसका प्रकटीकरण है। मुझे गर्व है कि बीजेपी—एनडीए की सरकारें समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी और महिलाएं, इन सभी वर्गों का बहुत विशेष ध्यान रख रही है।

कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष ने देश की जनता की रक्षा के लिए शुरू किये गए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बाधा उत्पन्न करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्यमंत्रियों ने 'मेड इन इंडियाश वैक्सीन को बदनाम किया और वैक्सीनेशन ड्राइव को खराब करने के हर प्रयास किये लेकिन आज वे वैक्सीनेशन—वैक्सीनेशन कर रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने भारत के वैक्सीनेशन अभियान को बदनाम करने के प्रयास किये और हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल उठाये। चिंता मत कीजिये, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर व्यक्ति को समय रहते वैक्सीन लगेगा।

श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार की तत्परता और देशवासियों की सजगता के कारण हम दुनिया के अनेक देशों के मुकाबले संक्रमण दर को सबसे कम रखने में सफल हुए हैं। पाजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट, रिकवरी में काफी तेजी आई है और हम कोरोना को परास्त करने के रास्ते पर अग्रसर हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समस्त देशवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हर अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचानी है और वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाना है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अभियान में पूरे मनोयोग से लगेगा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा की ये पहल काफी सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि किसान मोर्चा आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव लेता रहेगा और किसानों की भलाई के साथ—साथ आम जनता की सहायता के लिए भी काम करता रहेगा।

कोरोना पीड़ितों की सेवा के लिए गांव-गांव जाएगी भाजपा,15 जुलाई तक अभियान

खबर का सार : 10 जून से प्रदेश में शुरू हुए सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जहां एक हजार से अधिक पीएचसी गोद लिए जा रहे हैं, वहीं हर जिले में एक से दो पोस्ट कोविड सेंटर संचालित किए जाएंगे। यह जानकारी कमल ज्योति को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने देते हुये बताया कि, संक्रमण के बाद लोगों की समस्याओं में बढ़ोतरी न हो इसके लिये भाजपा कार्यकर्त्ता लोगों को जागरुक करने के लिये अभियान चलायेंगे।

अब विस्तार से पढे : उत्तर प्रदेश में कोरोना के दूसरे संक्रमण के बाद पीड़ितों को चिकित्सीय सुबिधायें दिलाने के लिये भाजपा कोरोना पीड़ितों की सेवा और सद्भाव के जरिये जनता के बीच पहुंच रही है। यह अभियान सेवा ही संगठन 2.0 10 जून से प्रदेश में शुरू हो चुका है। सेवा ही संगठन 2.0 अभियान के तहत भाजपा के सांसदों, विधायकों सरकार के मंत्रियों और पदाधिकारियों द्वारा जहां एक हजार से अधिक पीएचसी गोद लिए जा रहे हैं, वहीं हर जिले में एक से दो पोस्ट कोविड सेंटर संचालित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत भाजपा का प्रयास है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हर कमी को पूरा किया जाए।

हम सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अनेक विषयों, जैसे वेंटिलेटर आपरेट करना तथा अन्य सामान्य चिकित्सकीय जानकारी के लिए वालंटियर की आवश्यकता भी पड़ी है। ऐसे में भाजपा ने यह तय किया है कि पार्टी तथा पार्टी के सभी मोर्चे पूरे प्रदेश भर में हेल्थ वालंटियर तैयार करने के अभियान को चलाएंगे।

कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए लोगों का ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इन सेवा कार्यों के जरिये पार्टी प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां, कोरोना प्रबंधन, श्रमिकों व प्रवासियों की मदद सहित अनेक योजनाओं की जानकारी न सिर्फ जनता के बीच लेकर जाएंगे, बल्कि अब तक योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जुड़वाकर लाभांवित भी कराएंगे। 15 जुलाई तक चलने वाले अभियानों के जरिये 98 संगठनात्मक जिलों के गांवों और शहरों में जनता के बीच पहुंचने की योजना है।

टीकाकरण अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला तथा प्रदेश मंत्री संजय राय को प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि जिलों में पोस्ट कोविड सेंटर का संचालन किया जाएगा। इसमें कोरोना संक्रमण से निगेटिव हुए लोगों में कमजोरी, शुगर, शरीर में दर्द या अन्य दुष्प्रभावों के लिए चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। पोस्ट कोविड सेंटर संचालन के लिए महामंत्री अनूप गुप्ता और प्रदेश मंत्री रामचंद्र कनौजिया को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि पार्टी के सांसद, विधायक, आयोगों, निगमों, बोर्डों के अध्यक्षों की ओर से पीएचसी–सीएचसी को गोद लेकर सक्षम स्वास्थ्य केंद्र बनाने का बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत और प्रदेश मंत्री त्रयंबक त्रिपाठी को प्रभारी नियुक्त किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले इसके लिए उनकी सहायता भी करेंगे। इस अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य तथा प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंश को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कोरोना के कारण जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है उन परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंग और उनकी मदद का प्रयास करेंगे।

इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ अभियान में आदर्श स्थापित किए हैं। आपदा के दौर में मोदी–योगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार और संगठन जनता की समस्याओं और संकट के समाधान में जुटे हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन को मूलमंत्र मानकर अपनी क्षमता के साथ जन–जन की सेवा में लगा है।

भाजपा कार्यकर्ताओं से सेवा कार्य करने की प्रेरणा ले विपक्ष : स्वतंत्र देव सिंह

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सात वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने 28 मई से लेकर 30 मई तक 7253 यूनिट रक्तदान किया। सेवा ही संगठन अभियान की समीक्षा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना काल में कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये इस कार्य की सराहना करते हुए विपक्षी दलों को भाजपा कार्यकर्ताओं से सेवा कार्य करने की प्रेरणा लेने की सलाह दी।

यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में कहा कि, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की छवि चुनावी कार्यकर्ता के रूप में थी, लेकिन भाजपा ने सेवा कार्यों तथा सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से छवि को बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एक–एक पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता ने सेवा को ही संगठन बनाने का काम किया।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भोजन पैकेट, राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां आदि जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। इसी कड़ी में कार्यकर्ता रक्तदान भी कर रहे हैं। सरकार की सातवीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष अभियान के पहले दिन मोर्चों ने मिलकर रक्तदान शिविर लगाए और बड़ी संख्या में रक्तदान किया।

प्रदेश महामंत्री एवं रक्तदान कार्यक्रम संयोजक जेपीएस राठौर ने बताया कि तीन दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम के तहत पहले दिन प्रदेश में कुल 1904 यूनिट रक्त दान किया गया। युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अनुसूचित तथा अल्पसंख्यक मोर्चों ने मिलकर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। 29 व 30 मई को भी रक्तदान शिविर का आयोजन जिला स्तर पर किया गया जिसमें दोनों दिनों में 5349 यूनिट रक्तदान किया गया। इस तरह से कुल 7253 यूनिट रक्तदान किया गया है।

पश्चिम क्षेत्र रक्तदान में अव्वल : रक्तदान कार्यक्रम की क्षेत्रवार जानकारी देते हुए महामंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र में 2189, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 973, ब्रज क्षेत्र में 1651, अवध क्षेत्र में 859, गोरखपुर क्षेत्र में 882 तथा काशी क्षेत्र में 859 यूनिट रक्त दान किया गया।

कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें : राधा मोहन सिंह

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने सेवा ही संगठन अभियान के तहत लोगों की सहायता और उनकी मदद के लिए योजनापूर्वक सेवा कार्यों को और अधिक गति से करने का निर्णय लिया है। सेवा कार्यों को गति देते हुए पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित कर सेवा कार्यों को गति देने के लिए योजना बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने शनिवार रात लखनऊ पहुंचकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल के साथ सेवा कार्यों को लेकर चर्चा की। इससे पहले शनिवार को स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल की मौजूदगी में सपंन्न हुई अवध क्षेत्र की बैठक में पार्टी द्वारा तय किये गए सेवा कार्यों को चलाने के लिए योजना बनी।

राधा मोहन सिंह ने रविवार को पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस की आपदा में जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं। जिसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद संक्रमण दर को नियंत्रित करते हुए टीकाकरण अभियान में भी प्रदेश अग्रणी रहा है। यही कारण है जनता का विश्वास योगी सरकार के प्रति और दृढ़ हुआ है और लोकप्रियता और समर्थन में भी व्यापक विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना से लेकर सभी नियामक संस्थाओं ने भी की है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जब अपने घरों में दुबककर भ्रामक व नकारात्मकता फैलाने में व्यस्त थे उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन का अभियान शुरू किया। जनता के बीच में जाकर भाजपा कार्यकर्ता उनके सुख-दुख के साझीदार बन रहे है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में पार्टी के सांसदों, विधायकों, आयोग-बोर्ड, निगमों के अध्यक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेंगे। पार्टी का यह भी प्रयास होगा कि स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी समन्वय स्थापित कर उनसे भी इस कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया जाय।

वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा जागरूक

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी ने बताया कि जो लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हुए हैं, ऐसे पोस्ट कोविड मरीजों को जिन्हें स्वास्थ्य सम्बधी परेशानियां अभी भी हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए डाक्टरों की टीम बनाकर उनका भी सहयोग करना है। पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। साथ ही ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन अधिक से अधिक कराने के प्रयास करने हैं जिनका सामाजिक सम्पर्क अधिक होता है। जैसे आटो, टैक्सी ड्राइवर, फल-सब्जी विक्रेता, दूग्ध विक्रेता, डिलीवरी बॉय यानि वे लोग जो सेवा दाता कार्यों से जुडे है उनका जल्द से जल्द वैक्शिनेशन हो जाए इसका प्रयास करना है।

कार्यकर्ता करें योजनाओं का प्रचार-प्रसार

साथ ही कोरोना महामारी से बचाव व संक्रमण से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर लोगों को योजनाओं से अवगत कराएं और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता करें।

गांव-गांव जाएगी सरकार, ब्लाकों में प्रभारी मंत्री करेंगे प्रवास

सेवा कार्यों के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं व टीकाकरण शिविर का निरीक्षण स्वच्छता और वृक्षारोपण व्यवस्था का जायजा लेंगे

संक्षेप में : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में कहा कि अपने प्रवास के दौरान किसी योजना का शुभारंभ करने, सहायता राशि वितरण के साथ ही लोगों से बैठक लेकर स्थानीय लोगों से फीडबैक लें।

विस्तार में बैठक : मिशन–2022 विजय के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री जून और जुलाई माह के दौरान गांव–गांव में जाकर सेवा कार्य करेंगे और वहीं रहकर जनता के बीच सरकार और संगठन की थाह भी लेंगे। सभी मंत्री कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से किए गए सफल प्रबंधन की जानकारी भी जनता को देंगे।

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को जून–जुलाई तक अपने प्रभार वाले जिले के हर ब्लाक में प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की मौजूदगी में लोक भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद यूपी में दूसरी लहर को सबसे जल्दी नियंत्रित किया गया है। प्रतिदिन चार लाख टेस्ट कराए जा रहे हैं, सबसे कम पाजिटिव रेट और सबसे अधिक रिकवरी दर भी यूपी की है। यहां कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना से मृत्यु पर अनुग्रह राशि दी जा रही है। प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी वालों सहित अन्य श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई है।

मंत्री और संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता संयुक्त रूप से सरकार के कोरोना प्रबंधन की उपलब्धि को जनता के बीच जाकर बताएं। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जिले के ब्लाक में प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करें। प्रवास के दौरान किसी योजना का शुभारंभ करने, सहायता राशि वितरण के साथ बैठक लेकर स्थानीय लोगों से फीडबैक लें। मुख्यमंत्री ने सेवा कार्यों के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं व टीकाकरण शिविर का निरीक्षण करने, स्वच्छता और वृक्षारोपण व्यवस्था का जायजा लेने के निर्देश दिए।

इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने योगी मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार व संगठन की ओर से संयुक्त रूप से किए गए प्रयास सफल भी हुए हैं। महामारी के दौर में सरकार व संगठन ने गांव–गांव जनसेवा के कार्य किए हैं। ब्लाक में रहने वाले प्रमुख जाति–समाज के प्रभावशाली लोगों, प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े लोगों से मुलाकात कर उन्हें कोरोना प्रबंधन में मिली सफलता और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में किए गए प्रबंधन और संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का प्रस्तुतीकरण भी दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, महेंद्र सिंह, सुरेश राणा सहित अन्य मंत्री उपस्थित थे।

वैश्विक कारपोरेट कर की दर में कमी से भारत को सबसे अधिक लाभ

ब्रिटेन में छह जून 2021 को सात विकसित औद्योगिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान के समूह जी–7 के वित्त मंत्रियों की बैठक में वैश्विक कारपोरेट कर की दर को न्यूनतम 15 फीसदी रखे जाने संबंधी समझौते पर सहमति बनी है। यह कर समझौता वैश्विक कर परिदृश्य में दशकों का सबसे बड़ा और दूरगामी परिवर्तन साबित हो सकता है। ऐसा समझौता भारत के लिए लाभप्रद होगा। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें कारपोरेट कर की दर में इस बढ़ोतरी के बाद और वृद्धि देख सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष (2020–21) में देश में एफडीआई रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया था।

यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत के एफडीआई परिदृश्य पर सऊदी अरब उन शीर्ष निवेशकों में उभरकर सामने आया है, जिसका निवेश प्रतिशत सबसे ज्यादा बढ़ा है। अमेरिका और ब्रिटेन से एफडीआई प्रवाह क्रमशः 227 प्रतिशत और 44 प्रतिशत बढ़ा है। जहां तक राज्यों का सवाल है, एफडीआई हासिल करने में गुजरात शीर्ष पर है, इसके बाद महाराष्ट्र व कर्नाटक का स्थान है। देश में एफडीआई आने के विभिन्न सेक्टरों के मद्देनजर 44 फीसदी एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर सेक्टर में आया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 13 फीसदी व सर्विस सेक्टर में आठ फीसदी एफडीआई आया है।

हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020–21 में एफडीआई 19 प्रतिशत बढ़कर 59.64 अरब डालर हो गया। इस दौरान इक्विटी, पुनर्निवेश आय और पूंजी सहित कुल एफडीआई 10 प्रतिशत बढ़कर 81.72 अरब डालर हो गया। 2019–20 में एफडीआई का कुल प्रवाह 74.39 अरब डालर था। उल्लेखनीय है कि भारत में एफडीआई का प्रमुख केंद्र सिंगापुर बना हुआ है। कुल एफडीआई में सिंगापुर की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है। इसके बाद 23 प्रतिशत के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर और नौ प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मारीशस तीसरे स्थान पर है।

इस बात पर विचार करें कि जब पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट रही है, इसके बावजूद विदेशी निवेशकों द्वारा भारत को एफडीआई के लिए प्राथमिकता क्यों दी गई है, तो हमारे सामने कई चमकीले तथ्य उभरकर सामने आते हैं। देश में एफडीआई बढ़ने का एक बड़ा कारण मोदी सरकार द्वारा उद्योग–कारोबार को आसान बनाने के लिए किए गए कई ऐतिहासिक सुधार हैं। जीएसटी लागू हुआ है। कारपोरेट कर में बड़ी कमी की गई है और बड़े आयकर सुधार लागू किए गए हैं। देश में आधार बायोमेट्रिक परियोजना, रेलवे, बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया गया है।

स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के कारण लाकडाउन में ई–कामर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान, आनलाइन एजुकेशन तथा वर्क फ्राम होम की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए इंटरनेट के उपयोगकर्ता, देश भर में डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाओं के डिजिटल होने से अमेरिकी टेक कंपनियों सहित दुनिया की कई कंपनियां भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रिटेल सेक्टर के ई–कामर्स बाजार की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए निवेश के साथ आगे बढ़ी हैं।

'ईज आफ डुइंग बिजनेस' नीति के तहत देश में कारोबार को गति देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। पिछले छह–सात वर्षों में 1,500 से ज्यादा पुराने व बेकार कानूनों को खत्म कर नए कानूनों को लागू किए जाने और विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर सुधारों के दम पर निवेश के मामले में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। यदि हम चालू वित्त वर्ष 2021–22 में पिछले वित्त वर्ष के तहत प्राप्त किए गए करीब 82 अरब डॉलर के एफडीआई से अधिक की नई ऊंचाई चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि वर्तमान एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया जाए।

खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुंचा वैश्विक निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी

कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच देश से कृषि उत्पादों के निर्यात में रिकार्ड बढ़ोतरी की उम्मीद दिख रही है। इस महामारी ने अकल्पनीय मानवीय और आर्थिक आपदाएं निर्मित की हैं, पर इसी के बीच भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कृषि के निर्यात बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में अप्रैल, 2021 को केंद्रीय भंडारों में करीब 7.72 करोड़ टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार अनुमानित है, जो बफर आवश्यकता से करीब तीन गुना है। ऐसे में वर्ष 2021 में वैश्विक मांग के अनुरूप खाद्यान्न निर्यात सरलतापूर्वक बढ़ाया जा सकेगा।

21 अप्रैल को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020–21 के अप्रैल से फरवरी के 11 महीनों के दौरान देश से 2.74 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। यह साल भर पहले के 2.31 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 16.88 फीसदी ज्यादा है। इसी अवधि में कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का आयात भी तीन फीसदी बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पर भारत के पक्ष में कृषि व्यापार संतुलन बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यदि हम कृषि निर्यात के आंकड़ों को देखें, तो पाते हैं कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज के निर्यात में अप्रैल से फरवरी 2021 के दौरान तेज वृद्धि हुई है। चूंकि दुनिया के कई खाद्य निर्यातक देश महामारी के कारण चावल, गेहूं, मक्का और अन्य कृषि पदार्थों का निर्यात करने में पिछड़ गए, ऐसे में भारत ने इस अवसर का दोहन करके कृषि निर्यात बढ़ा लिया। भारत से गेहूं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। गेहूं का निर्यात साल भर पहले के 425 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। खासतौर से अफगानिस्तान को 50 हजार टन और लेबनान को 40 हजार टन गेहूं निर्यात किया गया है। गैर बासमती चावल का निर्यात 13,030 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,277 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। भारत ने ब्राजील, चिली जैसे कई नए बाजारों में पकड़ बनाई है। खास बात यह है कि चीन ने भी भारत से बासमती चावल खरीदना शुरू किया है। खाद्यान्न के अलावा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में भी डालर मूल्यों के आधार पर अच्छी वृद्धि हुई है।

महामारी के बीच दुनिया भर में लाकडाउन और कोविड–19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने से खाद्य पदार्थों के वैश्विक खरीदारों के साथ जुड़ना मुश्किल था। ऐसे में कृषि निर्यात संबंधी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने विशिष्ट वर्चुअल वैश्विक कृषि व्यापार मेलों और देश के कृषि पदार्थों के निर्यातकों के साथ वैश्विक खरीदारों की अलग–अलग इंटरैक्शन मीट आयोजित की। यही नहीं एपीडा ने कृषि निर्यात के विभिन्न विभागों से निकट समन्वय स्थापित किया और निर्यात बढ़ाने के लिए दिन–प्रतिदिन के आधार पर कृषि निर्यातकों के साथ संपर्क बनाए रखा।

उल्लेखनीय है कि कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ाने में भारत के कृषि, अनुसंधान और कृषि मानकों की वैश्विक मान्यता ने भी अहम भूमिका निभाई है। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के बीच कृषि निर्यात और बढ़ाए जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक, फसल वर्ष 2020–21 के लिए मुख्य फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान में खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुंचते हुए 3033.4 लाख टन अनुमानित है। कृषि निर्यात को रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कई कृषि निर्यात अवरोध दूर किए जाने की जरूरत है।

उदाहरण के लिए, पशुधन के मामले में आयात करने वाले कई देश मांस और दूध से बने उत्पादों के लिए फूड ऐंड माउथ रोग मुक्त स्थिति की शर्त लगा रहे हैं। कुछ देशों की शर्त है कि निर्यात की जाने वाली उपज कीट मुक्त क्षेत्रों से होनी चाहिए। इन अवरोधों को दूर करने के लिए संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से वार्ताएं आगे बढ़ाने की जरूरत है। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने जो सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं, उनका क्रियान्वयन भी लाभप्रद होगा।

सेवा संगठन अभियान 2.0

मेरा बूथ मेरा टीकाकरण के साथ वैक्सीनेशन केन्द्रों पर चलेगा अभियान

भारतीय जनता पार्टी 10 जून से 15 जुलाई 2021 तक मेरा बूथ मेरा टीकाकरण अभियान को आरंभ कर चुकी है। इसके लिये क्षेत्र एवं जिला पदाधिकारी इस अभियान हेतु कार्यरत है। इसके लिये हर जिले में 18 से 44 वर्श एवं 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिये, कितने वैक्सीनेशन सेन्टर बनाये गये हैं, उनकी सूची बनाकर जागरुकता को गति देनी है।

इस अभियान के संयोजक प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्त्ता पदाधिकारी सभी वैक्सीनेशन केन्द्रों पर आने वाले लोगों को चाय–पानी की सुविधा प्रदान करना एवं उनकी सहायता कर रहे हैं। चाय–पानी की व्यवस्था हेतु व्यापार मण्डल, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब इत्यादि से सहायता हेतु सम्पर्क करके गति प्रदान की जा रही है। जिले के सभी मण्डल, शक्ति केन्द्र (सेक्टर), बूथ तक सरकार द्वारा लगाये जा रहे कोविड से बचाव हेतु निःशुल्क टीका के लिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि, संगठन के पदाधिकारी (वर्तमान एवं पूर्व), जनप्रतिनिधि, एन.जी.ओ. एवं समाजसेवी संगठनों (जैसे–रामलीला समिति, विद्यालयों की समितियां, मठ–मन्दिर के पुजारी, सिक्ख संगत, दुर्गा पूजा समिति, व्यापार मण्डल, अधिवक्ता संघ आदि) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महानगरों/जिला मुख्यालयों पर जिस वर्ग के सर्विस प्रोवाइडरर्स अधिक संख्या में हों, उनकी सूची बनाना, (जैसे–ई–रिक्शा चालक, ऑटो–टैक्सी चालक, कैब चालक, फल मण्डी, सब्जी मण्डी, विभिन्न सेवाओं से जुड़े गार्ड (वॉचमैन), किराना दुकानदार, श्रमिक अड्डे, घूम कर या दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाले, दूध विक्रेता, फूड डिलेवरी ब्वाय, टिफिन सर्विस, नाई, धोबी, मोची इत्यादि सेवाओं से जुड़े लोगों के बीच संपर्क किया जा रहा है।

इस अभियान के सह संयोजक और प्रदेश मंत्री संजय राय ने बताया कि वैक्सीनेशन हेतु युवा मोर्चा एवं आई. टी. के 50 कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करने हेतु उनकी वर्चुअल ट्रेनिंग एवं इस टीम को ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकरण हेतु लगाया गया है। ट्रेनिंग के उपरांत प्रत्येक मण्डल पर 02 या 02 से अधिक प्रशिक्षित कार्यकर्ता को लैपटाप /कम्प्यूटर /स्मार्ट–फोन के माध्यम से वेबसाइट WWW.COWIN.COM एवं आरोग्य सेतु एप, पर ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति केन्द्र के किसी एक गांव का चयन कर प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को आई.डी. के आधार पर पंजीकरण कर आस–पास के वैक्सीनेशन केन्द्रों पर उन्हे भेजा रहा है। इस हेतु शक्ति केन्द्र के सभी बूथ अध्यक्षों को लगाया गया है। इसके लिये कार्यकर्ता दिवसवार मण्डल व उससे ऊपर के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों की केन्द्रवार 2–2 कार्यकताओं की टीम कार्य कर रही है।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा का बृहद वृक्षारोपण

भारतीय जनता पार्टी विश्व योग दिवस पर विभिन्न आयोजनों के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने आगामी अभियानों की कार्ययोजना तैयार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से भारतीय योग की महत्ता को पूरे विश्व ने स्वीकार किया और 21 जून 2015 से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा। यह समस्त भारतीयों के लिए गौरव का क्षण था। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष प्रत्येक मंडल पर विश्व योग दिवस मनाएगी। मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड–19 के नियमों का पालन करते हुए पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा नागरिक योग करेंगे। उन्होंने कहा कि 23 जून को देश की एकता और अखंडता के लिए आजाद भारत में पहला बलिदान डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। पार्टी अपने प्रेरणापुंज डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 23 जून से 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर वृहद वृक्षारोपण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक–एक कार्यकर्ता ने राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। अन्य राजनीतिक दलों में राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र चुनावी कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा–समर्पण के साथ ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़कर रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता तथा जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने का काम करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि पार्टी इन अभियानों के साथ ही सेवा ही संगठन अभियान के तहत वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता, पोस्ट कोविड सेंटर का संचालन जैसे कार्य साथ ही करती रहेंगी।

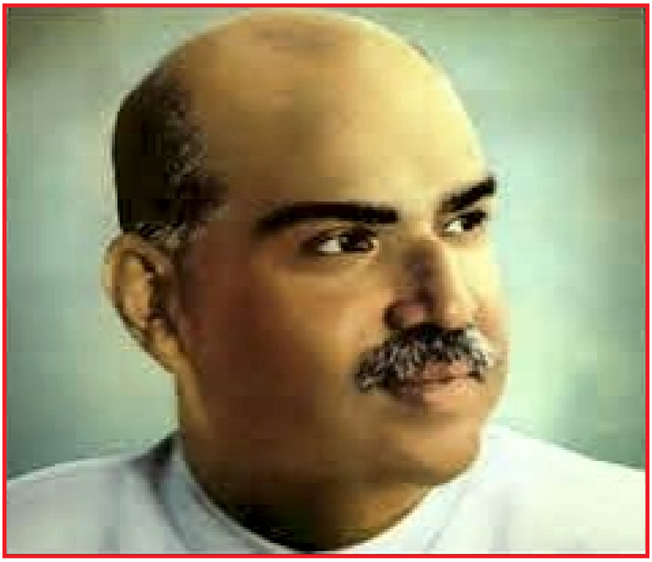

पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी प्रदेश में 1918 मंडलों में 21 जून को विश्व योग दिवस पर योग के कार्यक्रम आयोजित करेंगी। विश्व योग दिवस कार्यक्रम के प्रदेश प्रमुख प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई, सतपाल सैनी, सुरेंद्र नागर, प्रदेश मंत्री देवेश कोरी रहेंगे। श्री शुक्ला ने बताया कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पार्टी प्रदेश के 163000 से अधिक बूथों पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी। आगामी 23 जून से 6 जुलाई तक चलने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम कि प्रदेश प्रमुख प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, सुनीता दयाल, प्रदेश मंत्री चंद्र मोहन व शंकर गिरी रहेंगे

28 जून को वर्चुअल होगी भाजपा कार्यसमिति बैठक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी एवं प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील कुमार बंसल ने पार्टी की संगठनात्मक संरचना एवं अन्य गतिविधियों से सम्बंधित बिंदुओं पर चर्चा हेतु एक दिवसीय वर्चुअल प्रदेश कार्यसमिति का आयोजन 28 जून को करना निश्चित किया है। प्रदेश महामंत्री एवं अभियान के संयोजक जेपीएस राठौर ने बताया कि इसके साथ ही जिला कार्यसमितियों एवं मण्डल कार्यसमितियों को भी आभासी माध्यम से करना है। अभियान में प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य एवं प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी को भी लगाया गया है।

श्री राठौर ने बताया कि प्रदेश कार्यसमिति की आभासी बैठक में चार सत्र रहेंगे। जिसमें उद्घाटन सत्र, शोक प्रस्ताव सत्र, राजनीतिक प्रस्ताव सत्र,आगामी कार्यक्रम सत्र, अभियान एवं 2022 के चुनाव पर चर्चा भी की जायेगी। इसके बाद समापन सत्र होगा। इस प्रदेश कार्यसमिति में अपने–अपने जिला केन्द्र पर सभी अपेक्षित कार्यकर्ता एक साथ जुड़ेंगे।

जिला कार्यसमिति - (01-15 जुलाई' 2021)

सभी जिला अपने कार्यसमिति की बैठक 01–15 जुलाई के बीच कोई एक दिन निश्चय कर जिला प्रभारी से वार्ता करके करेंगे जिसकी पूर्व जानकारी प्रदेश को देनी है। जिला कार्यसमिति में भी 04 सत्र रहेंगे। सभी सत्र के लिये अलग–अलग वक्ताओं के प्रस्तावित नाम भी प्रदेश से जाएंगे।

मण्डल कार्यसमिति - (16-31 जुलाई' 2021)

प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य ने बताया कि मंडल कार्यसमितियां भौतिक रूप से आयोजित की जा सकेंगे क्यों कि उनकी संख्या प्रोटोकाल के अनुरूप है। सभी मण्डलों को अपनी कार्यसमिति 16 से 31 जुलाई के बीच में करना है। मण्डल की कार्यसमिति प्रत्यक्ष स्वरूप में रहेगी। कोविड–19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए कार्यसमिति का स्थान एवं तारीख तय करना है। इस कार्यसमिति में जिले से वक्ता भेजे जायेंगे। मण्डल अध्यक्ष/मण्डल प्रभारी जिले से जाने वाले वक्ता की जानकारी प्राप्त करेंगे। मण्डल की कार्यसमिति भी 04 सत्रों में रहेगी। प्रदेश एवं जिले की कार्यसमिति के विषयों पर मण्डल की कार्यसमिति में चर्चा की जायेगी। कार्यक्रम का स्थान एवं समय तय हो जाने पर जिला व क्षेत्रीय कार्यालय को इससे अवगत कराना है।

ओबीसी आयोग में जसवन्त सिंह सैनी और एससी-एसटी आयोग में राम बाबू हरित बने अध्यक्ष

अब तक उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष रहे सहारनपुर के जसवन्त सिंह सैनी को अध्यक्ष नामित किया गया है। श्री सैनी भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री भी रहे हैं। उनके साथ ही लखीमपुर के हीरा ठाकुर तथा गाजीपुर के प्रभुनाथ चौहान को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 25 सदस्य भी नामित किये गये है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री मंत्री अनिल राजभर ने पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नामित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के निर्देश पर उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री अनिल राजभर ने कहा है किइस गठन से इससे प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में आसानी होगी। सरकार ने आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 25 सदस्य नामित किये हैं।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सहारनपुर के जसवन्त सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। लखीमपुर के हीरा ठाकुर तथा गाजीपुर के प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लोगों न्याय दिलाने के लिए 25 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर से जगदीश पांचाल, मेरठ से हरवीर पाल, अमरोहा से चन्द्र पाल खड़गवंशी, गौतमबुद्धनगर से विजेन्द्र भाटी, आगरा से राकेश कुशवाहा, झांसी से जगदीश साहू, चित्रकूट से राम रतन प्रजापति, अयोध्या से बलराम मौर्य एवं श्री रघुनंदन चौरसिया, चन्दौली से शिव मंगल बियार, बलिया से देवेन्द्र यादव, देवरिया से डा0 त्रिपुणायक विश्वकर्मा, गोरखपुर से राम जियावन मौर्य, फतेहपुर से राधेश्याम नामदेव, अम्बेडकर नगर से धर्मराज निषाद, कानपुर से अरूण पाल एवं रमेश वर्मा निषाद, मैनपुरी से श्रीमती ममता राजपूत, मथुरा सेघनश्याम लोधी, सहारनपुर से श्रीमती सपना कश्यप, बुलन्दशहर से रवीन्द्र राजौरा, बस्ती से शिवपूजन राजभर, मुरादाबाद से गिरीश वर्मा, प्रयागराज से जवाहर पटेल तथा वाराणसी से नरेन्द्र पटेल को पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नामित किया गया है।

एससी–एसटी आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सदस्य नामित

उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य हेतु 18 लोगों को नामित किया गया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के0 रविन्द्र नायक द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार आयोग के अध्यक्ष हेतु आगरा निवासी डॉ0 राम बाबू हरित को नामित किया गया है। उपाध्यक्ष पद हेतु शाहजहाँपुर निवासी मिथिलेश कुमार व सोनभद्र निवासी रामनरेश यादव को नामित किया है।

आयोग के नामित सदस्यों में साध्वी गीता प्रधान सम्भल, ओमप्रकाश नायक अलीगढ़, कमलेश पासी वाराणसी, रमेश तूफानी लखनऊ, शेषनाथ आचार्य बलिया, तीजा राम आजमगढ़, अनीता सिद्धार्थ जौनपुर, रामआसरे दिवाकर फर्रूखाबाद, श्याम अहेरिया मथुरा, मनोज सोनकर वाराणसी, श्रवण गोण्ड सोनभद्र, अमरेश चन्द्र चेरो सोनभद्र, किशनलाल सुदर्शन कानपुर, के0के0 राज इटावा को शामिल किया गया है।

नए प्रदेश पदाधिकारी घोषित

भाजपा टीम में एक उपाध्यक्ष, दो प्रदेश मंत्री घोषित

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने शनिवार 19 जून को भाजपा की प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जिसमें मऊ से अरविन्द कुमार शर्मा को उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना मिश्र को प्रदेश मंत्री और अमित बाल्मीकी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

इस घोषणा के बाद भाजपा की प्रदेश टीम में खाली सभी पदों को भर दिया गया है।

भाजपा के मोर्चा पदाधिकारी घोषित

कामेश्वर सिंह किसान मोर्चा और प्रांशुधर द्विवेदी युवा मोर्चा अध्यक्ष घोषित

महिला मोर्चा अध्यक्ष सांसद गीताशाक्य, एसटी मोर्चा कौशल किशोर और एसटी मोर्चा की कमान डा. संजय गोंड को दी गई है। डा. गोंड पूर्व में अनुसूचित जन जाति आयोग के महामंत्री रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने 19 जून शानिवार को भाजपा के सभी छह मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश मंत्री पद पर कार्यरत रहे फर्रुखाबाद के प्रांशुधर द्विवेदी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि महिला मोर्चा की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद औरैया की गीता शाक्य को बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष गाजियाबाद के नरेन्द्र कश्यप को बनाया गया है। जबकि किसान मोर्चा की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश मंत्री गोरखपुर के कामेश्वर सिंह को सौंपी गई है। अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दोबारा सांसद कौशल किशोर को दी गई है जबकि अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष बलिया के संजय गोंड को बनाया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी मेरठ के कुं बासित अली को दी गई है।

प्रदेश आई.टी. टीम घोषित

श्री कामेश्वर मिश्रा को आई.टी. विभाग का प्रदेश संयोजक तथा श्री मांगीलाल चौधरी को आई.टी. विभाग का प्रदेश सहसंयोजक घोषित किया गया है।

श्री अंकित चन्देल को सोशल मीडिया का प्रदेश संयोजक तथा श्री हर्ष चतुर्वेदी, श्री शशि शेखर सिंह, श्री गौरव वार्ष्णेय तथा श्री सौरभ मरोदिया को सोशल मीडिया का प्रदेश सहसंयोजक घोषित किया है।

प्रदेश मीडिया टीम घोषित

श्री मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। जबकि श्री हिमांशु दुबे, श्री धर्मेन्द्र राय, श्री प्रियंक पाण्डेय व श्री अभय सिंह को प्रदेश सहमीडिया प्रभारी बनाया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समीर सिंह, श्री मनीष शुक्ला, श्री हीरो बाजपेयी, श्री आलोक अवस्थी, श्री अशोक पाण्डेय, श्री जुगल किशोर, श्रीमती अनिला सिंह, श्री राकेश त्रिपाठी, श्री प्रशान्त वशिष्ठ, श्री संजय चौधरी, श्री आनंद दुबे, श्रीमती साक्षी दिवाकर, श्री आलोक वर्मा तथा सुश्री महामेधा नागर को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता घोषित किया है।

आदि युग से “योग”

भारत में योग 10000 वर्ष पूर्व के ज्ञात इतिहास से चला आ रहा है। योग परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय संस्कृति है। योग के साक्ष्य पूर्व वैदिक काल और हड़प्पा–मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से भी पूर्व से मौजूद हैं। वेद–पुराणों में योग का महत्व ''सर्ववेदार्थ सारोऽत्र वेद व्यासेन भाषितः। योग भाष्यभिषोणातो मुमुक्षणमिद गर्त।।'' से मिलता है। व्यास भाष्य में योग–विद्या को स्वीकार किया गया है। गीता में कहा गया है, 'योगः कर्मसु कौशलम्'। यानी जो योग की साधना करता है, उसके कर्मो में कुशलता आती है, निपुणता आती है।

योग जीवन को अच्छे ढंग से जीने का विज्ञान है। संस्कृत के शब्द 'युज' से बना है, जिसका अर्थ है मिलन, अर्थात् आत्मीय चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ सामंजस्य। वेद युग में हमारे ऋषियों ने इसके माध्यम से लोगों को लाभांवित किया। पौराणिक परंपराओं में भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है और पार्वती उनकी पहली शिष्या। योग का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। योग से ऋषियों ने तप के अनुष्ठान से ब्रह्माण्ड के अनेक रहस्यों से साक्षात्कार किया हैं।

योग से व्यक्ति की चेतना, ब्रह्मांड चेतना से जुड़ती है। यह चिंतन, सोच एवं कार्य के बीच एकीकरण करता है।

सिंधू–सरस्वती सभ्यता में योग

सदियों से योग की कई शाखाएं विकसित हुई हैं। लेकिन इसका विकास पूर्ण रूप से भारत में पूर्व वैदिक काल में हुआ। जब मानव सभ्यता का आरंभ हो रहा था। वेदों और पुराणों में तो योग पर विस्तार से बात हुई है, लेकिन उसके साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मौजूद रहे हैं। इन सभ्यताओं में कई ऐसी मुहरें साक्ष्य के तौर पर मिलीं हैं। मुहरों परविभिन्न तरह की मुद्राओं का उभार है, जो आसन और प्राणायाम की मुद्राएं हैं। सिंधू–सरस्वती सभ्यता से मिले इन सिक्कों को भगवान पशुपति की आकृति माना जाता हैं जो योग मुद्रा में हैं।

विश्व में योग को जिस रूप को आज हम देखते हैं, उसका पहली बार उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। योगाभ्यास का सबसे पुराना उल्लेख प्राचीनतम उपनिषद– बृहदअरण्यक में है। वेद मंत्रों में प्राणायाम अभ्यास का वर्णन है और छांदोग्य उपनिषद में इसका जिक्र है। बृहदअरण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादी गार्गी के बीच संवाद में सांस लेने की कई तकनीकें, स्वास्थ्य से जुड़े आसन और ध्यान का उल्लेख है। अथर्ववेद

में संन्यासियों के समूह ने शरीर के विभिन्न आसनों के महत्व को समझाया वही आगे चलकर योग के रूप में विकसित हुआ।

भारतीय दर्शन में योग का सबसे विस्तृत उल्लेख पतंजलि योगसूत्र में मिला है। जो अष्टांग योग का आधार बनी। जीवन में व्यक्ति निर्माण के लिए अष्टांग योग के दो चरण यम एवं नियम दो व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण में सहायक सूत्र है। यम हमें सामाजिक एवं नियम स्व निर्माण में सहायक है। लगभग 200 ईपू में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग–सूत्र की रचना की। महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। योग के उक्त आठ अंगों में ही सभी योग का समावेश है।

अष्टांग योग या राजयोग

अष्टांग योग अर्थात योग के आठ अंग। ऋषि पतंजलि ने योग की समस्त विद्याओं को आठ अंगों में श्रेणीबद्ध किया है। यह आठ अंग हैं– (1) यम (2)नियम (3)आसन (4) प्राणायाम (5)प्रत्याहार (6)धारणा (7) ध्यान (8)समाधि। वर्तमान में योग के तीन अंग प्रचलन में हैं– आसन, प्राणायाम–ध्यान।

महर्षि पतंजलि का 'योगसूत्र' योग दर्शन का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन है। योगदर्शन के चार भाग को पाद कहा गया है, जो कि चार भागों में विभाजित है– समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद।

प्रथम पाद का मुख्य विषय चित्त की विभिन्न वृत्तियों के नियमन से समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है। **द्वितीय पाद** में पाँच बहिरंग साधन– यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का विवेचन है। **तृतीय पाद** में अंतरंग तीन धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। **चतुर्थ** कैवल्यपाद मुक्ति की वह परमोच्च अवस्था है, जहाँ एक योग साधक अपने मूल स्रोत से एकाकार हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं 'योगाश्चित्त वृत्तिनिरोधः'। अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का संयमन है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि ने द्वितीय और तृतीय पाद में जिस अष्टांग योग साधन का उपदेश दिया है, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं।

यम कायिक, वाचिक तथा मानसिक इस संयम के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जैसे अपरिग्रह आदि पाँच आचार विहित हैं। इनका पालन न करने से व्यक्ति का जीवन और समाज दोनों ही दुष्प्रभावित होते हैं।

नियम मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करते हेतु नियमों का विधान किया गया है। इनके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान का समावेश है।

आसन पतंजलि ने स्थिर बैठने की क्रिया को आसन कहा है। परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठयोग का एक मुख्य विषय ही है। इनसे संबंधित 'हठयोग प्रतीपिका' 'घरेण्ड संहिता' तथा 'योगाशिखोपनिषद्' में विस्तार से वर्णन मिलता है।

प्राणायाम योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है।

प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियाँ मनुष्य को बाह्यभिमुख करती हैं।

धारणा चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है।

ध्यान जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती।

समाधि यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है।

समाधि की दो श्रेणियाँ हैं : सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात। सम्प्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। असम्प्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है।।

योग का प्रथम अंग यम

दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं– योगाश्चित वृत्ति निरोध अर्थात योग चित्त की वृतियों का संयमन है। योग दर्शन के पाद 2 सूत्र 30 में यम के संबंध में बताया गया है। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मच्य्यार्परिग्रहा यमारू अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है। यम से मन मजबूत और पवित्र होता है तथा मानसिक शक्ति बढ़ती है।

यम के पांच प्रकार हैं : – 1– अहिंसा,2– सत्य ,3– अस्तेय, 4– ब्रह्मचर्य, 5– अपरिग्रह

(1) अहिंसा : आत्मवत् सर्वभूतेषुश् अर्थात सभी को स्वयं के जैसा समझना ही अहिंसा है। मन, वचन एवं कर्म से हिंसा न करना ही अहिंसा माना गया है, लेकिन अहिंसा का इससे भी व्यापक अर्थ है स्वयं के साथ अन्याय या हिंसा करना भी अपराध है। क्रोध करना, लोभ, मोह पालना, किसी वृत्ति का दमन करना, शरीर को कष्ट देना आदि सभी स्वयं के साथ हिंसा है।

(2) सत्य: सत्य का आमतौर पर अर्थ माना जाता है झूठ न बोलना। सत् और तत् धातु से मिल कर बना है सत्य, जिसका अर्थ होता है यह और वह – अर्थात यह भी वह भी, क्योंकि सत्य पूर्ण रूप से एकतरफा नहीं होता।

(3) अस्तेय: इसे अचौर्य भी कहते हैं अर्थात चोरी की भावना नहीं रखना, न ही मन में चुराने का विचार लाना! धन, भूमि, संपत्ति, विद्या आदि किसी भी ऐसी वस्तु जिसे पुरुषार्थ से या स्व से अर्जित नहीं किया गया या किसी ने भेंट या पुरस्कार में नहीं दिया, को लेने के विचार मात्र से ही अस्तेय खंडित होता है।

(4) ब्रह्मचार्य: इंद्रिय निग्रह कर संयमित रखना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है उस एक ब्रह्म की चर्चा करना अर्थात उसके ही ध्यान में रमना और उसकी चर्चा करते रहना ही ब्रह्मचर्य है! ।

(5) अपरिग्रह: इसे अनासक्ति भी कहते हैं अर्थात किसी भी विचार, वस्तु और व्यक्ति के प्रति मोह न रखना ही अपरिग्रह है। आसक्ति से ही आदतों का जन्म भी होता है। मन, वचन और कर्म से इस प्रवृत्ति को त्यागना ही अपरिग्रही होना है!

योग का द्वितीय अंग नियम

आष्टांग योग के दूसरे अंग नियम भी पाँच प्रकार के होते हैं (1) शौच, (2) संतोष, (3) तप, (4) स्वाध्याय और (5) ईश्वर प्राणिधान।

शौच: शौच मतलब स्वच्छता शारिरीक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं ।जिवन को सुखी स्वस्थ तथा आनन्दमय

संतोष: संतोष की सिद्धि के लिए और निराश करने वाली स्थितियों से बचने का प्रयास किया जाना

तप : तप से शरीर कुंदन बनता है और आत्मिक उर्जा का संचरण बना रहता है

स्वाध्याय : स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना।

ईश्वर प्राणिधान : ईश्वर के सन्निकट पहुंचने के लिए सायुज्य की स्थिति बनाने का प्रयास करना ताकि आत्मा का परमात्मा का एकाकार स्थापित किया जा सकें।

प्राणायाम के तहत अपने श्वसन की जागरूकता पैदा करना और अपने अस्तित्व के प्रकार्यात्मक या महत्वापूर्ण आधार के रूप में श्वसन को अपनी इच्छाग से विनियमित करना शामिल है। यह अपने मन की चेतना को विकसित करने में मदद करता है तथा मन पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। यह नासिकाओं, मुंह तथा शरीर के अन्यव द्वारों, इसके आंतरिक एवं बाहरी मार्गों तथा गंतव्यों के माध्याम से श्वास – प्रश्वास की जागरूकता पैदा करके किया जाता है। आगे चलकर, विनियमित, नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित श्वास के माध्यम से इस परिदृश्य को संशोधित किया जाता है जिससे यह जागरूकता पैदा होती है कि शरीर के स्थान भर रहे हैं (पूरक), स्थान भरी हुई अवस्था में बने हुए हैं (कुंभक) और विनियमित, नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित प्रश्वोस के दौरान यह खाली हो रहा है (रेचक)।

इस प्रकार, योग का लक्ष्यि आत्म–अनुभूति और कष्टों से मुक्ति पाना है जिससे मोक्ष या कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है। योग का अभिप्राय आंतरिक विज्ञान से भी है जिसमें कई तरह की विधियां हैं जिनसे मानव स्वयं को साकार कर सकता है और अपनी नियति को वश में कर सकता है।

मुखर्जी के सपनों का हुआ जम्मू-कश्मीर एक विधान एक निशान का सपना साकार

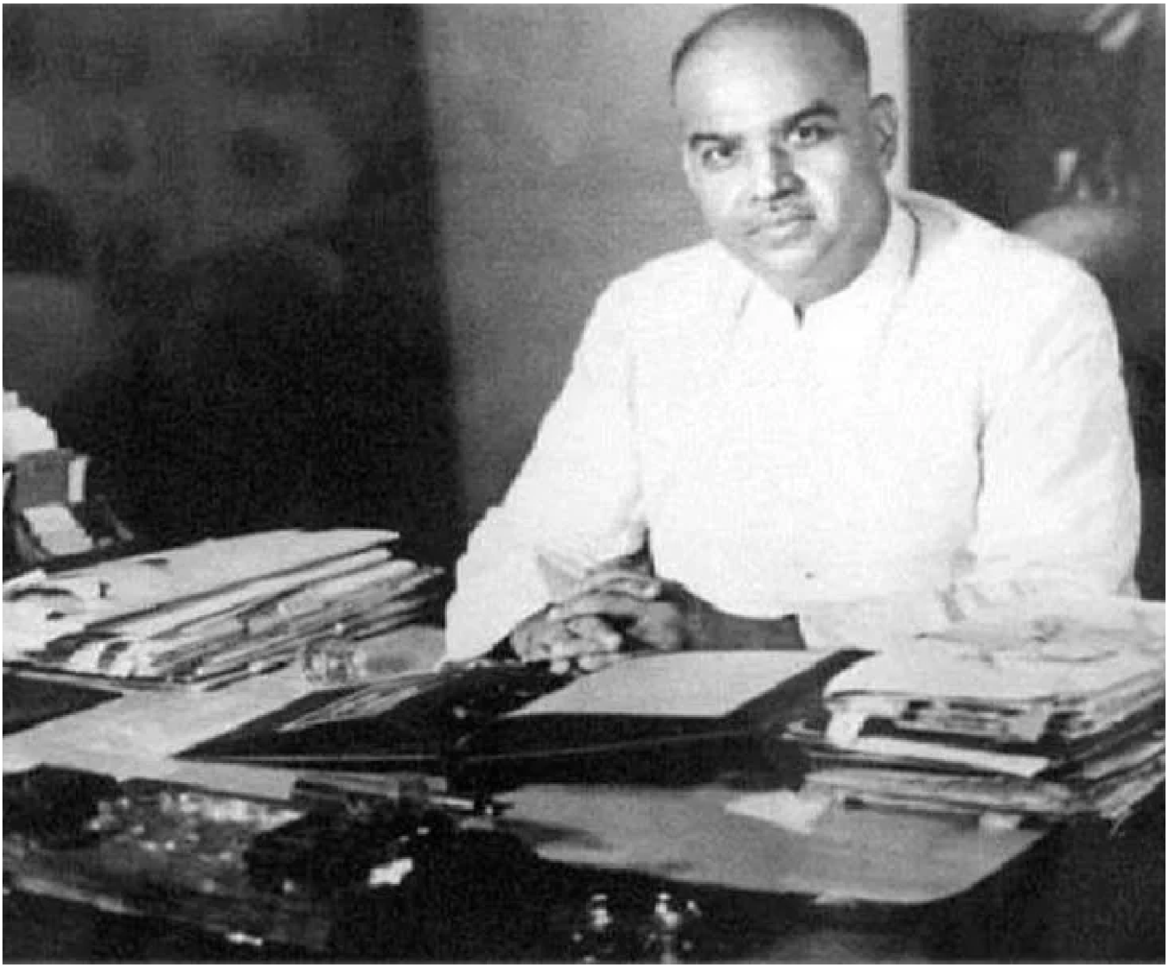

2019 में जम्मू कश्मीर में अनुछेद 370 और 35ए को खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अनुछेद 370 और 35ए को हटाने की मांग की थी जिसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया। सरकार ने देशवासियों की सात दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। वो सपना जो जम्मू–कश्मीर को एक करने के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जिसके लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया, आखिरकार वह सपना आंखों के सामने सच हो गया है। इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमितशाह ने अप्रतिम कार्य किया है।

मुखर्जी ने वर्ष 1953 में दो विधान, दो निशान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था जो 2019 में पूरा हो सका है। जम्मू–कश्मीर के लिए वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने वह सारे प्रयत्न किये जो पूर्व की सरकारों को करना

चाहिये था लेकिन सत्ता में लगातार रहने वाली कांगेसी सरकारों ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था।

लखनपुर में परमिट प्रणाली के विरोध में जब मुखर्जी ने विशाल मार्च निकाला था तो उन्हें जम्मू में प्रवेश करने पर यहां की तत्कालीन सरकार ने रोका था। यही नहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कश्मीर में एक जगह पर कैदी बनाकर रखा गया। अगर सरकार चाहती तो उन्हें लखनपुर से वापस भी लौटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय उन पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 40 दिन तक कारागार में रखा गया।

भाजपा का भावनात्मक संबंध

कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। इस जुड़ाव के प्रणेता जनसंघ के संस्थापक और कभी जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1953 की तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार की निषेधाज्ञा संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने के कारण मुखर्जी को जेल में डाल दिया गया था, जहां संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी। मुखर्जी का विरोध कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ था। गौरतलब है कि जनसंघ ही वर्तमान भाजपा का पहला राजनीतिक अवतार था।

जम्मू–कश्मीर का भारत में विलय एक महत्वपूर्ण और लंबी चलने वाली प्रक्रिया था। राज्य की हैसियत को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच बातचीत आजादी के पांच साल बाद 1952 के गर्मियों तक चलती रही। नेहरू और उनके मंत्रियों और अब्दुल्ला के बीच राज्य की स्वायत्ता पर एक समझौता हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि जम्मू–कश्मीर का अपना अलग झंडा होगा। इतना ही नहीं इसके तहत यह भी तय हुआ कि आंतरिक गड़बड़ी के मामले में भारत सरकार राज्य सरकार की अनुमति के बिना वहां सेना नहीं भेजेगी। इसके अलावा राज्य से बाहर के निवासी जम्मू–कश्मीर में जमीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। हालांकि, शेख इससे भी ज्यादा चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि केवल जम्मू–कश्मीर ही यह तय करेगा कि भारत को राज्य के मामले में कौन सी शक्तियां दी जाएं और देश का सुप्रीम कोर्ट किस हद तक राज्य पर लागू होगा। अब्दुल्ला ने यहां तक कहा था कि अगर कर्ण सिंह राज्य विरोधी ताकतों के साथ मिलते हैं तो उन्हें भी उनके पिता महाराजा हरि सिंह की तरह सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा।

इस मामले का पहली बार विरोध प्रजा परिषद ने किया। इसे अब्दुल्ला काफी हीन भावना से देखते थे। 1951 में अब्दुल्ला की नेशनल कान्फ्रेंस ने यहां की विधानसभा की सभी 75 सीटें जीत ली थीं। परिषद ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। हालांकि परिषद का समर्थन करने वालों में सबसे आगे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी ने नारा दिया था– श्एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

कश्मीर मुद्दे पर छोड़ दी थी कैबिनेट

मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे पर ही नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 21 अक्टूबर, 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। संसद में मुखर्जी ने लगातार जम्मू–कश्मीर में नेहरू सरकार की नीति की आलोचना की थी। उन्होंने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया था। मुखर्जी ने कहा था कि कम से कम जम्मू और लद्दाख को देश के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए।

जम्मू–कश्मीर में चली गई जान

मुखर्जी का कश्मीर मामले पर सरकार का विरोध 1953 में भी जारी रहा। उन्होंने नेहरू सरकार से पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर को वापस मांगने की भी मांग की। उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों को भी आजाद करने की मांग रखी। इन सभी मांगों के साथ उन्होंने 8 मई, 1953 को श्रीनगर के लिए निकले। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनके आंदोलन को रोकने के आदेश जारी किया और श्यामा प्रसाद को 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। श्यामा प्रसाद को श्रीनगर की जेल में रखा गया था। जेल में श्यामा प्रसाद ने हिंदू दर्शन पढ़ा और पत्र लिखे। जून की शुरुआत में वह बीमार हो गए। 22 जून को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 23 जून, 1953 को उनका निधन हो गया।

इस तरह मुखर्जी की कश्मीर संबंधी मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए भावनात्मक मुद्दा बन गईं और पार्टी तभी से इन मांगों को अपने एजेंडे में शामिल करते हुए आगे बढ़ती रही है।

ए के त्रिपाठी

श्रीनगर में रहस्मयी मौत? ये सच छिपाया नेहरू ने?

डॉ श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने अपना सार्वजनिक जीवन शिक्षाविद् के रूप में आरंभ किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वे उपकुलपति रहे। तदुपरांत उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। बंगाल की प्रांतीय राजनीति में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता से टक्कर ली, हिंदू महासभा के नेता के रूप में हिंदुओं के न्यायोचित हितों और अधिकारों का समर्थन किया और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया, राष्ट्रीय स्वातंर्त्य आंदोलन में भाग लेकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, देश का विभाजन होने की अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाने पर बंगाल का विभाजन करवाया और बंगाल के बड़े हिस्से को पाकिस्तान में जाने से बचा लिया। आजादी के बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के रूप में भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी और पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के उत्पीड़न और निष्क्रमण के मुद्दे पर नेहरू की नीतियों से असहमत होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राजनीति में कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प की आवश्यकता अनुभव कर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। कश्मीर के प्रश्न पर डॉ. मुकर्जी ने शेख अब्दुल्ला की अलगाववादी नीतियों का विरोध कियाय धारा 370 की समाप्ति तथा जम्मू–कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। कश्मीर का प्रश्न अभी भी अनसुलझा ही है। लेकिन उसका एक चरण धारा 370 के रूप में पूरा हो गया है।

डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की रहस्मयी मौत के तुरंत पश्चात् उस समय के तात्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नम–नेत्रों से डॉ मुखर्जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि, " अपने सार्वजनिक जीवन में वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को एवं अपनी अंदरूनी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करने में कभी डरते नहीं थे। खामोशी में कठोरतम झूठ बोले जाते हैं, जब बड़ी गलतियां की जाती हैं, तब इस उम्मीद में चुप रहना अपराध है कि एक–न–एक दिन कोई सच बोलेगा।"

विडम्बना यह है कि तात्कालीन सत्ता के खिलाफ जाकर सच बोलने की जुर्रत करने वाले डॉ. मुखर्जी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज भी देश की जनता उनकी रहस्यमयी मौत के पीछे की सच को जान पाने में नाकामयाब है। डॉ. मुखर्जी इस प्रण पर सदैव अडिग रहे कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। उन्होंने सिंह–गर्जना करते हुए कहा था कि, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेगा– नही चलेगा। मुखर्जी का ये सपना उनके अपनों ने अब पूरा कर दिखाया है। 2019 में जम्मू कश्मीर के माथे से वह कलंक हट गया।

उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में यह

प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारत सरकार से बिना परमिट लिए हुए जम्मू–कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। डॉ. मुखर्जी इस प्रावधान के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि, नेहरू जी ने ही ये बार–बार ऐलान किया है कि जम्मू व कश्मीर राज्य का भारत में 100 फीसदी विलय हो चुका है, फिर भी यह देखकर हैरानी होती है कि इस राज्य में कोई भारत सरकार से परमिट लिए बिना दाखिल नहीं हो सकता। मैं नही समझता कि भारत सरकार को यह हक है कि वह किसी को भी भारतीय संघ के किसी हिस्से में जाने से रोक सके क्योंकि खुद नेहरू ऐसा कहते हैं कि इस संघ में जम्मू व कश्मीर भी शामिल है।

उन्होंने इस प्रावधान के विरोध में भारत सरकार से बिना परमिट लिए हुए जम्मू व कश्मीर जाने की योजना बनाई। इसके साथ ही उनका अन्य मकसद था वहां के वर्तमान हालात से स्वयं को वाकिफ कराना क्योंकि जम्मू व कश्मीर के तात्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार ने वहां के सुन्नी कश्मीरी मुसलमानों के बाद दूसरे सबसे बड़े स्थानीय भाषाई डोगरा समुदाय के लोगों पर असहनीय जुल्म ढाना शुरू कर दिया था।

नेशनल कांफ्रेंस का डोगरा–विरोधी उत्पीड़न वर्ष 1952 के शुरूआती दौर में अपने चरम पर पहुंच गया था। डोगरा समुदाय के आदर्श पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने बलराज मधोक के साथ मिलकर जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद् पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी ने डोगरा अधिकारों के अलावा जम्मू व कश्मीर राज्य का भारत संघ में पूर्ण विलय की लड़ाई, बिना रुके, बिना थके लड़ी। इस कारण से डोगरा समुदाय के लोग शेख अब्दुल्ला को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे।

शेख अब्दुल्ला के दिमाग में जो योजनाएं थीं, उनके मुताबिक जम्मू व कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जा सकता था, जिसका अपना संविधान, राष्ट्रीय विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट और झंडा होगा। प्रजा परिषद् के नेताओं ने किसी तरह उस संविधान के प्रारूप की कापी हासिल कर ली, जिसके कारण भी वे शेख अब्दुल्ला की नजरो में चढ़ गए। उस समय के तात्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बीएन मलिक ने अपनी किताब 'माई इयर्स विद नेहरू कश्मीर' में लिखा है कि शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि सारे डोगरा कश्मीर छोड़कर भारत चले जाएं, और अपनी जमीन उन लोगों के लिए छोड़ दें, जिन्हें शेख अब्दुल्ला प्राणपन से चाहते थे।

डॉॅ. मुखर्जी बिना परमिट लिए हुए ही 8 मई, 1953 को सुबह 6.30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में अपने समर्थकों के साथ सवार होकर पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए निकले। उनके साथ बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, टेकचंद, गुरुदत्त वैध और कुछ पत्रकार भी थे। रास्तें में हर जगह डॉॅ. मुखर्जी की एक झलक पाने एवं उनका अभिवादन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता था। डॉॅ. मुखर्जी ने जालंधर के बाद बलराज मधोक को वापस भेज दिया और अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गुरदासपुर (जिला, जिसमे पठानकोट आता है) के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपनी पहचान बताई और कहा कि 'पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि आपको पठानकोट न पहुंचने दिया जाए। मैं अपनी सरकार से निर्देश का इंतजार कर रहा हूं कि आपको कहां गिरफ्तार किया जाए? हैरत की बात यह निकली कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, न तो अमृतसर में, न पठानकोट में और न ही रास्ते में कहीं और, अमृतसर स्टेशन पर करीब 20000 लोग डॉॅ.मुखर्जी के स्वागत के लिए मौजूद थे।

पठानकोट पहुंचने के तुरंत बाद गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर, जो उनका पीछा कर रहे थे, ने उनसे मिलने की इजाजत मांगी। उन्होंने डॉॅ. मुखर्जी को बताया कि उनकी सरकार ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे उन्हें और उनके सहयोगियों को आगे बढ़ने दें और बिना परमिट के जम्मू व कश्मीर में प्रवेश करने दें। उस अफसर को खुद हैरानी हो रही थी कि उसे जो आदेश मिलने वाले थे, वे पलट कैसे दिए गए। उसे तथा वहां मौजूद अन्य किसी को भी इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी, जिसके अनुसार डॉॅ. मुखर्जी को जम्मू व कश्मीर में गिरफ्तार किये जाने की योजना बन चुकी थी ताकि वे भारतीय

सर्वोच्च न्यायलय के अधिकार—क्षेत्र से बाहर पहुँच जाएं। उनका अगला ठहराव रावी नदी पर बसे माधोपुर की सीमा के पास चेकपोस्ट था।

रावी पंजाब की पांच महान नदियों में से एक थी, जो पंजाब और जम्मू व कश्मीर की सीमा बनाते हुए बीच से बहती थी। नदी के आर—पार जाने के लिए सड़कवाला एक पुल था, और राज्यों की सरहद इस पुल के बीचों—बीच थी। जैसे ही डॉ.मुखर्जी की जीप ब्रिज के बीच में पहुंची, उन्होंने देखा की जम्मू व कश्मीर पुलिस के जवानों का दस्ता सड़क के बीच में खड़ा है। जीप रुकी और तब एक पुलिस अफसर, जिसने बताया कि वह कठुआ का पुलिस अधीक्षक है, उसने राज्य के मुख्यसचिव का 10 मई, 1953 का एक आदेश सौपा, जिसमे राज्य में उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। लेकिन मैं जम्मू जाना चाहता हूँ ! डॉ मुखर्जी ने कहा।

इसके बाद उस पुलिस अफसर ने गिरफ्तारी का आदेश अपनी जेब से निकाला, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी किया गया था और जिस पर जम्मू व कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक पृथ्वीनंदन सिंह का 10 मई का दस्तखत था, जिसमे कहा गया था डॉ.मुखर्जी ने ऐसी गतिविधि की है, कर रहे हैं या करनेवाले हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति के खिलाफ है, अतः उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है।

प्रश्न यह उठता है कि यदि उनकी तथाकथित गतिविधियों से सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति को इतना ही बड़ा खतरा था, तो उन्हें जम्मू व कश्मीर के सीमा में प्रवेश करने से पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जैसा कि गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने डॉ.मुखर्जी को इस बारे में बताया था? उन्हें पठानकोट या उससे पहले ही गिरफ्तार किए जाने की योजना क्यों बदल दी गई? उन्हें आगे बढ़ने ही क्यों दिया गया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं।

डॉ.मुखर्जी को जिस जगह बंदी बनाया गया था, वह वाकई एक बहुत छोटा सा मकान था, जिसके आसपास कुछ भी नहीं था— निशात बाग के करीब, लेकिन श्रीनगर शहर से काफी दूर, जिसे एक उपजेल बना दिया गया था। इस मकान तक पहुंचने के लिए खड़ी सीढियां चढ़नी पड़ती थीं, खासकर उनके खराब पैर की वजह से यह और भी मुश्किल हो जाता होगा।

इस मकान का सबसे बड़ा कमरा दस फीट लम्बा और ग्यारह फीट चौड़ा था, जिसमे डॉ.मुखर्जी को बंदी बनाया गया था। वहीं किनारे के दो छोटे—छोटे कमरों में उनके साथ बंद गुरुदत्त वैध और टेकचंद को रखा गया था। शहर से कोई डाक्टर तभी आ सकता था, जब उसे विशेष रूप से बुलाया जाता। बांग्ला भाषा में लिखी गई उनकी द्वारा चिट्ठियों की विशेष अनुवादक द्वारा जांच कराई जाती थी। शेख अब्दुल्ला ने यह आदेश दे रखा था कि डॉ.मुखर्जी को कोई अतिरिक्त सहूलियत तब—तक न दी जाए, जब तक वे खुद आदेश न दें।

इधर, जेल में रहने के दौरान उनके किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को उनसे मिलने नहीं दिया गया, यहां तक कि उनके बड़े बेटे अनुतोष की अर्जी भी ठुकरा दी गई। वह जेल में प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे, जो कि उनके बारे में जानकारी का एक अच्छा स्त्रोत हो सकता था परन्तु शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनकी मौत के बाद उस डायरी को जब्त कर लिया और बार—बार गुजारिश के बावजूद भी अभी तक लौटाया नहीं गया है। 24 मई को पंडित नेहरू और डॉ.कैलाशनाथ काटजू आराम करने श्रीनगर पहुंचे पर उन लोगों ने डॉ.मुखर्जी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछना भी उचित नहीं समझा

22 जून की सुबह उनकी तबियत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जेल अधीक्षक को सूचित किया गया। काफी विलम्ब से वह एक टैक्सी (एम्बुलेंस नहीं) लेकर पहुंचे और वह डॉ.मुखर्जी को उस नाजुक हालात में भी उनके बेड से चलवाकर टैक्सी तक ले गए। उनके बाकी दो साथियों को उनके साथ उनकी देखभाल करने के लिए अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें कोई निजी नर्सिंग होम में नहीं बल्कि राजकीय अस्पताल के स्त्री प्रसूति वार्ड में भरती कराया गया।

एक नर्स जो कि डॉ.मुखर्जी के जीवन के अंतिम दिन उनकी सेवा में तैनात थी, ने डॉ.मुखर्जी की

बड़ी बेटी सविता और उनके पति निशीथ को काफी आरजू–मिन्नत के बाद श्रीनगर में एक गुप्त मुलाकात के दौरान यह बताया था कि उसी ने डॉ. मुखर्जी को वहां के डाक्टर के कहने पर आखिरी इंजेक्शन दिया था। उसने बताया कि जब डॉ मुखर्जी सो रहे थे तो डाक्टर जाते–जाते यह बता कर गया कि, डॉ मुखर्जी जागें तो उन्हें इंजेक्शन दे दिया जाए और उसके लिए उसने एम्प्यूल नर्स के पास छोड़ दिया।

इस तरह कुछ देर बाद जब डॉ.मुखर्जी जगे तो उस नर्स ने उन्हें वह इंजेक्शन दे दिया। नर्स के अनुसार जैसे ही उसने इंजेक्शन दिया डॉ.मुखर्जी उछल पड़े और पूरी ताकत से चीखे, जल जाता है, हमको जल रहा है। नर्स टेलीफोन की तरफ दौडी ताकि डाक्टर से कुछ सलाह ले सके परन्तु तब तक वह मूर्छित हो चुके थे और शायद सदा के लिए मौत की नींद सो चुके थे। पंडित नेहरू जो डॉ.मुखर्जी की मृत्यु के दौरान लन्दन में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी में हिस्सा ले रहे थे, ने बाम्बे एअरपोर्ट पर उतरने के पश्चात भी इस त्रासदी पर कुछ भी नहीं बोले जिसने उनकी अनुपस्थिति में पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था।

डॉ. मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने नेहरू के 30 जून, 1953 के शोक सन्देश का 4 जुलाई को उत्तर देते हुए पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनके बेटे की रहस्मयी परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग की। जवाब में पंडित नेहरु ने बड़ी मीठी–मीठी बातें लिखीं, दुखियारी मां के लिए आकंठ करुणा की अभिव्यक्ति कीय परन्तु जांच की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने जवाब देते हुए यह लिखा कि, मैंने कई लोगों से इस बारे में मालूमात हासिल किए हैं, जो इस बारे में काफी कुछ जानते थे। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं एक स्पष्ट और इमानदार नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि इसमें कोई रहस्य नहीं है और डॉ.मुखर्जी का पूरा ख्याल रखा गया था।

यहां सबसे बड़ा विचारनीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर पंडित नेहरू ने जांच की मांग को खारिज क्यों कर दिया? क्या उन्हें नैतिक, राजनैतिक या संवैधानिक किसी भी अधिकार के तहत इस प्रकार का फैसला सुनाने का हक था? क्या कोई गुप्त बात थी अथवा इस घटना के पीछे कोई साजिश थी जिसके जांच उपरांत बाहर आ जाने का डर था? ये सारे प्रश्न इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि जब कभी भी एक मशहूर शख्सियत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, अथवा वह गायब होता है, तब एक जांच जरूर होती है। इस तरह के कम से कम तीन कमीशन नेताजी सुभाषचंद्र बोस के गायब होने की जांच करने के लिए बनाए गए।

ये कमीशन थे शाहनवाज कमीशन (1956), जीडी खोसला कमीशन (1970) और मनोज मुकर्जी कमीशन(1999)। महात्मा गांधी की हत्या की जांच कपूर कमीशन ने, इंदिरा गांधी कि हत्या की जांच ठक्कर कमीशन ने और राजीव गांधी की हत्या की दो कमीशन जेएस वर्मा कमीशन और एमसी जैन कमीशन ने जांच की।

यहां यह गौरतलब है कि ये सभी हत्याकांड (नेताजी के गायब होने को छोड़कर) सबके आंखों के सामने हुएय फिर भी कातिलों की पृष्ठभूमि और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की गई, लेकिन डॉ. मुखर्जी की अकाल मौत रहस्मयी परिस्थितियों में एक गुप्त जगह में, परिवार और दोस्तों से दूर, एक शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में हुई, जहां भारत के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तक नहीं था, बावजूद इसके आज तक इस घटना की औपचारिकता मात्र के लिए भी एक जांच नहीं हुई है।

क्या यह डॉ.मुखर्जी एवं उनके परिवार के साथ–साथ पूरे देश के साथ एक सरासर धोखा नहीं है? क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि उसके प्रिय नेता की मौत के पीछे का जिम्मेदार कारक कौन था?

नोट : उपरोक्त लेख के लिए सारे तथ्य त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे तथागत राय की किताब अप्रतिम नायक डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रभात प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2013 से ली गई है।

ए.के. त्रिपाठी

देश कभी नहीं भूलेगा वह काला दिन

कमल ज्योति ब्यूरो

1975 में 25 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी। रातोंरात लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के लोकतंत्र में यह काला दिन बनकर अंकित है। आपातकाल 1977 में 21 मार्च को हटाया गया। यह आपातकाल आजाद भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है।

आपातकाल लगते ही देश से लोकतंत्र का पतन हो गया। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। सरकार का विरोध करने वाले नागरिकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उन्हें कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी नहीं दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत मिले अधिकारों का इंदिरा गांधी ने गलत प्रयोग किया। जय प्रकाश नारायण, जार्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम स्वामी, अटल बिहारी वायपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, रामकृष्ण हेगड़े, एचडी देवेगौड़ा, एम करुणानिधि, जेबी पटनायक, ज्योति बसु, मधु दंडवते, जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया।

इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने संविधान के अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया। आपातकाल के दौरान अप्रैल, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बसी झोपड़ियों को गिराने का आदेश दिया। जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसमें कई लोगों की जान गई। देश के लोगों को इस घटना के बारे में विदेशी मीडिया बीबीसी से पता चला।

मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। विदेशी मीडिया के संवाददाताओं को निर्वासित कर दिया गया। मई, 1976 में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि आपातकाल विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाले सात हजार लोगों की गिरफ्तारी हुई।

शाह कमीशन की रिपोर्ट

भारत सरकार ने 1977 में आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों की पड़ताल करने के लिए शाह कमीशन का गठन किया। इस कमीशन की रिपोर्ट में सामने आया कि आंतरिक सुरक्षा बहाली अधिनियम और भारतीय सुरक्षा नियमों के तहत 1,10,806 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया।

स्वार्थ के आगे लोकतंत्र धराशायी

आपातकाल लगाते वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि खराब आर्थिक स्थिति और आंतरिक और बाहरी खतरों से देश को बचाने के लिए आपातकाल लगाया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि भारत नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी खुद खतरे में थीं, इसलिए उन्होंने आपातकाल का रास्ता चुना। अपने निजी स्वार्थ की रक्षा के लिए उन्होंने लोकतंत्र का हनन किया।

क्यों लगाया गया आपातकाल

1971 युद्ध के बाद देश का विकास सुस्त था। सूखा, बेरोजगारी और तेल संकट के चलते अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मजदूरों और छात्रों के बीच असंतोष की गहरी भावना पैठ गई। आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जार्ज फर्नांडिस ने अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल का आयोजन कराया जिससे 1974 में भारी गिरफ्तारियां हुईं और देश में हलचल मच गई।

इंदिरा गांधी की भ्रष्ट और निरंकुश सरकार के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन रैलियों का नेतृत्व शुरू किया। 12 जून, 1975 को राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले ने इंदिरा को डरा दिया। कोर्ट ने चुनावों में धांधली का हवाला देते हुए लोकसभा में इंदिरा गांधी के चयन को रद्द कर दिया। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।

इंदिरा गांधी को शक था कि उन्हें पद से हटाने के लिए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी ने इस आंतरिक क्लेश को जन्म दिया था।

जेपी ने 25 जून, 1975 को सत्याग्रह और रैली का आह्वान किया।

जब इंदिरा ने देखा कि हालात काबू से बाहर हैं तो देश को 21 महीने के लिए आपातकाल के हवाले कर दिया।

नया लोकतंत्र? सेंसर लागू... शांत रहें!

इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के बाद

अखबारों में संपादकीय स्तंभ खाली छोड़ दिया गया। यह सरकार की निरंकुश कार्यप्रणाली पर गहरा प्रहार था। इसके चलते मीडिया समूह के संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक्सप्रेस समूह, जागरण समूह, हिन्दू समूह पर सरकार का सबसे अधिक सितम टूटा। दरअसल आपातकाल ऐसी अवधि होती है जिसमें सत्ता की पूरी कमान प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश को आंतरिक, बाहरी या आर्थिक खतरा हो सकता है तो वह आपातकाल लागू कर सकता है। अब तक देश में तीन बार आपातकाल लागू हुआ है।

- 26 अक्टूबर, 1962 से 10 जनवरी, 1968 : तक भारत– चीन युद्ध
- 3 दिसंबर, 1971 से 21 मार्च 1977 : पाकिस्तान से युद्ध
- 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 : इंदिरा ने निजी स्वार्थ साधने को आपातकाल लगाया।
- वर्तमान हालात अलग
- तब दोनों सदनों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। लोकसभा में 352 और राज्यसभा में 523 सीटें। हाल की या आने वाली सरकारों में ऐसी बहुमत की बहळ्त कम संभावना है।
- तब क्षेत्रीय पार्टियां आज जितनी मजबूत नहीं थीं।
- आज राज्य भी आर्थिक व राजनीतिक रूप से कहीं अधिक आजाद हैं।
- न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है, जैसे 1975 में जब जीने और आजादी का अधिकार भी छीन लिया गया था।
- राष्ट्रपति को अधिकार देने वाले अनुच्छेद 352 को पहले से अधिक सुरक्षित किया गया है।
- सोशल मीडिया और कनेक्टीविटी के चलते अब खबरों पर नियंत्रण संभव नहीं है।
- वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की पहचान है, ऐसे में किसी के लिए ऐसा कदम उठाना संभव नहीं है।

पुलिस जिसको चाहती थी, पकड़कर हवालात में बंद कर देती थ नियम–कानूनों की धज्जियां उड़ रही थी। पर अब ऐसा संभव नहीं हैं।

पच्चीस छब्बीस जून की आधी रात तक दिल्ली से सारे बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिये गए थे या अपने ही घर में नजरबंद कर दिए गए। उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चल रहा था। जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों के अलावा युवजन बड़ी संख्या में जुट गया था। समाचार भेजने पर भी रोक लग गई। मीडिया पर पूरा सेंसाशिप लनगा दी गई। मीडिया को हर समाचार पहले सूचना विभाग को भेजना होता था, यदि वहां से वह पास होता˚ तभी आगे उसे भेजा जाता था। विधानमंडल और संसद में जो बोला जाता था वह भी प्री सेंसर के लिए भेजना पड़ता था। नेताओं की पकड़ धकड़ के साथ समाचार पत्रों के कार्यालयों पर भी निगरानी रखी जाने लगी। बहुत से समाचार पत्र बंद हो गए या बंद करा दिए गए ।एक अजब सा माहौल था। पुलिस जिसको चाहती थी पकड़ लेती थी। एफआइआर की छपी–छपाई प्रति पुलिस के पास रहती थी जिस पर केवल नाम और पता भरने के साथ ही अपराध के किसी बिंदु पर टिक लगा देना होता था। अभिव्यक्ति के सभी स्नोतों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भूमिगत गतिविधियां जारी रहीं जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आपातकाल से बड़ा काला अध्याय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी की सरकार ने मौलिक अधिकार तक छीन लिए थे। यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार भी वापस ले लिया गया था। पूरे देश ने एक निर्मम तानाशाही के अभिशाप को भुगता। लोकतंत्र पर इसका कितना निर्मम असर पहरा था, इसकी एक बानगी यह भी है कि प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी।

अखबारों में सेंसर बैठ गए थे, जो खबरों में कांट–छांट करते थे। ये सेंसर पुलिस के अफसर थे। अखबार सारे संपादकीय, लेख और खबरें इन सेंसरों के पास भेजने के लिए मजबूर किए गए थे। क्या यह एक लोकतंत्र में हो सकता है? ज्यादतियों का दूसरा प्रमाण लाखों लोगों की जबरन नसबंदी किया जाना था। लोगों को बस स्टार, बाजार–हर जगह से जबरदस्ती बसों में भरकर नसबंदी कैंपों तक ले जाया गया। हरियाणा के एक गांव का मामला उस समय खूब चर्चा में आया था। पुलिस ने समूचे गांव को घेर लिया और आठ से अस्सी साल तक के प्रत्येक पुरुष को नसबंदी कैंप तक ले जाया गया। देश में लोकतंत्र और जनता के बुनियादी अधिकारों की चिंता करने वाले सभी लोगों को आपातकाल के उन डराने वाले दिनों को कभी भूलना नहीं चाहिए।

दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
जून प्रथम 2021 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

सेवा ही संगठन

कार्यक्रम को सम्बोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी